



पायनियर

Established 1865

नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

www.dailypioneer.com

आभ्यन्तर

राष्ट्रीय-10

आगे तेजी से बढ़ेगी
अर्थव्यवस्था

जाड़े की धुंध की गिरफ्त में दिल्ली

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में कड़क की ठंड और घना कोहरा छाया रहा, जिससे वायु गुणवत्ता फिर से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई और पूरे शहर में दृश्यता में भारी कमी आई। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 433 रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है। अगले दो दिनों तक एक्यूआई के 'गंभीर' श्रेणी में रहने की उम्मीद है। दिल्ली के 35 निगरानी स्टेशनों में से 28 ने वायु गुणवत्ता को 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया, जबकि कुछ ने 450 अंक को पार कर लिया, जिसे 'गंभीर प्लस' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मंदिर मार्ग, जहांगीरपुरी, नरेला, नेहरू नगर, पटपड़गंज, पंजाबी बाग, रोहिणी, आईटीओ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, डीटीयू, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, मंदिर मार्ग, पूसा,

शदीपुर में निगरानी स्टेशनों ने एक्यूआई को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया। अलीपुर, आनंद विहार, अशोक विहार, बवना, बुराड़ी, सीआरआरआई मथुरा रोड, नॉर्थ कैम्प, ओखला फेज 2, सिरोफोर्ट, सोनिया विहार और विवेक विहार में एक्यूआई गंभीर प्लस श्रेणी में था। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, प्रदूषकों के प्रभावी फैलाव के लिए मौसम संबंधी स्थिति प्रतिकूल रहने की संभावना है। दिल्ली के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन था, जिसने पीएम 2.5 का 18.8 प्रतिशत योगदान दिया। पंजाब और हरियाणा में मौसम खत्म होने के कारण दिल्ली के प्रदूषण में पराती जलाने का कोई योगदान नहीं था। पीएम 2.5 प्राथमिक प्रदूषक रहा, जिसका स्तर शाम 4 बजे 252 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। इस बीच, धुंध और शीत लहर की स्थिति ने पूरे क्षेत्र में गंभीर व्यवधान पैदा कर दिया है। जिले के विभिन्न हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता

बहुत कम हो गई और यात्रियों के लिए चुनौतियां पैदा हो गई। आईएमडी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 5.30 बजे न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बाद में औसतन 5.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। पूसा में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आनंदनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नजफगढ़ में न्यूनतम तापमान थोड़ा अधिक 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में और गिरावट आने और कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के कारण दिल्ली हवाईअड्डा प्रशासन ने मंगलवार को कम दृश्यता प्रक्रिया लागू की। सफदरजंग हवाईअड्डे पर मध्यम कोहरा रहा। सफदरजंग हवाईअड्डे पर सुबह आठ बजे सबसे कम दृश्यता 350 मीटर दर्ज की गई, जो इसके बाद सुधर कर आठ बजकर तीस मिनट पर 400 मीटर हो गई हालांकि, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

(आईजीआईएफ) प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों से उड़ान संचालन प्रभावित नहीं हुआ है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइनों से नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए संपर्क करें। हवाई अड्डा प्रशासन ने एकपर पर पोस्ट किया, 'दिल्ली हवाई अड्डे पर कम दृश्यता प्रक्रियाएं लागू हैं। उड़ान संचालन सामान्य बना हुआ है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।'

इस बीच, दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत प्रदूषण विरोधी उपायों को फिर से लागू करने के बाद कक्षाएं संचालित करने के हाइब्रिड मोड पर स्विच कर दिया। संशोधित जीआरएपी कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कक्षा छह से नौ और 11 के छात्रों के लिए चरण 4 के तहत हाइब्रिड मोड (भौतिक और ऑनलाइन) में कक्षाएं संचालित होनी चाहिए। हालांकि, दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों को व्यक्तिगत रूप से स्कूल जाना होगा। दिल्ली ट्रेफिक पुलिस ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर अंकुश लगाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) चरण चार लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की जांच बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारी और सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की जांच बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारी और सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की जांच बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारी और सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की जांच बढ़ा दी है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर बरसा सुप्रीम कोर्ट

● परेशान घर खरीदारों की दुर्दशा पर कहा, गड़बड़ी के लिए आप जिम्मेदार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

परेशान घर खरीदारों की दुर्दशा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) से शिकायत निवारण के लिए प्रस्ताव पेश करने को कहा और समय पर जवाब दाखिल न करने पर उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार की पीठ ने जीएनआईडीए के रवैयें पर असंतोष व्यक्त किया और कहा, 'इस गड़बड़ी के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। बेशक, डेवलपर्स ने घर खरीदारों से पैसे कमाए हैं। लेकिन इससे आपके कृत्यों को माफ नहीं किया जा सकता।' पीठ ने कहा कि अगर जीएनआईडीए घर खरीदारों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई योजना रखें तो वे असंतोष को माफ इस पूरी 'गड़बड़ी' की सीबीआई जांच का आदेश दे सकती है। सीजेआई ने कहा, 'आप 10 दिनों में कोई योजना लेकर आए... अन्यथा हम सीबीआई जांच का आदेश देंगे... आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि घर खरीदारों के हितों को रखा हो। आप भी इस समस्या का हिस्सा हैं। आपने इस गड़बड़ी को होने दिया।' पीठ ने जीएनआईडीए को सुझाव



दिया कि वह पूरी जमीन अपने कब्जे में ले, परियोजनाओं का विकास करें और घर खरीदने वालों को प्लेट दे दें। जीएनआईडीए से विस्तृत हलफनामा मांगते हुए पीठ ने उसे जमीन के आवंटन की तारीख और निजी कंपनी के पक्ष में लीज डीड के निष्पादन की तारीख सहित जानकारी देने को कहा। घर खरीदने वालों के लिए एक व्यापक प्रस्ताव मांगने के अलावा, पीठ ने जीएनआईडीए से यह जानकारी देने को कहा कि जब डेवलपर्स ने परियोजनाओं की शर्तों का उल्लंघन किया तो जमीन का आवंटन रद्द क्यों नहीं किया गया। 800 से अधिक घर खरीदने वालों की ओर से पेश बरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि एक पीएसयू रुकी हुई परियोजनाओं को विकसित करने और जीएनआईडीए और अन्य को बकाया राशि का भुगतान करने को तैयार है, और इसके अलावा, किसी भी लेनदार या निवेशक को कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले से उत्पन्न 12 अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। एनसीएलएटी ने घर खरीदने वालों के एक समूह की याचिका को खारिज कर दिया था, जिन्होंने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिग्रहण के लिए अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट की बोली को एनसीएलटी की मंजूरी को चुनौती दी थी। एनसीएलएटी ने 8 जून, 2021 को अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट की समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लेनदारों की समिति ने 99 प्रतिशत बहुमत के साथ अल्फा कॉर्प के पक्ष में मतदान किया था। लंबी कानूनी लड़ाई के कारण, रियल्टी फर्म की पांच आवासीय परियोजनाएं, ग्रेटर नोएडा में तीन और गुरुग्राम में दो, रुकी हुई हैं, जिससे सैकड़ों घर खरीदार मुश्किल में हैं। इससे पहले, अल्फा कॉर्प ने कहा था कि वह ग्रेटर नोएडा में दिवालियापन प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहित अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तीन रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। (शेष पृष्ठ 9)

नीट-यूजी परीक्षा के लिए विकल्पों पर विचार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हर साल मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के बाद विवादों के बीच केंद्र ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी को पेन और पेपर मोड में आयोजित किया जाए या ऑनलाइन मोड में और इस संबंध में जल्द ही निर्णय होने की उम्मीद है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ दो दौर की बातचीत की है। वर्तमान में, नीट-यूजी ऑफलाइन - पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाती है - जिसमें छात्रों को ओएमआर शीट पर बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने होते हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के मामले में देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। 2024 में, रिकॉर्ड 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी।



में एक पूर्व-निवारक कदम के रूप में रद्द कर दिया गया। प्रधान ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) 2025 से कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करेगी, इसके बजाय केवल उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगले साल एजेंसी का पुनर्गठन किया जाएगा और नए पद सृजित किए जा रहे हैं।

यह कदम राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित लीक और सांदिग्ध लीक और अन्य गड़बड़ियों के कारण कई अन्य परीक्षाओं को रद्द करने के बाद इस साल की शुरुआत में गठित एक उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा सुधारों का हिस्सा है। देश में तकनीकी शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग में प्रधान ने कहा, NEET का प्रशासनिक मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय है और

से लगभग 56,000 सीटें सरकारी अस्पतालों में और लगभग 52,000 निजी कॉलेजों में हैं। दंत चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी नीट के परिणामों का उपयोग किया जाता है। नीट के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड पर स्विच करने का विचार नया नहीं है और इस पर पहले भी कई बार विचार-विमर्श किया जा चुका है। हालांकि, इस साल की शुरुआत में पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा सुधारों के लिए जोर आया। नीट और पीएचडी प्रवेश परीक्षा नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं के बीच केंद्र ने जुलाई में एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारु और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पैनल का गठन किया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है, 'प्रत्येक चरण में स्कोरिंग और रैंकिंग के लिए सीमा और परीक्षण उद्देश्यों तथा प्रयासों की संख्या आदि के साथ एक स्वीकार्य ढांचा विकसित किया जा सकता है।' उच्च स्तरीय पैनल द्वारा की गई सिफारिशों में प्रतिरूपण की जांच के लिए एक DIGI-EXAM प्रणाली, बहु-चरणीय और बहु-स्तरीय परीक्षण, परीक्षा केंद्र सार्वजनिक और ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करना शामिल है। पैनल ने DIGI-YATRA (शेष पृष्ठ 9)

दिल्ली के 30 से अधिक स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी



पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी के 30 से अधिक स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ई-मेल की जरिए मिली यह धमकी इस सप्ताह की दूसरी और नौ दिनों के अंदर पांचवीं ऐसी घटना है, जिससे दिल्ली के छात्र, कर्मचारी और अधिकारी दहशत में हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दक्षिणी दिल्ली के ड ईडिन स्कूल, सफदरजंग एनक्लेव के एंबियंस पब्लिक स्कूल, दिलशाद गार्डन के दिलशाद पब्लिक स्कूल और बाहरी दिल्ली के क्रिसेंट स्कूल समेत 30 से ज्यादा स्कूलों ने बताया कि उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के कुछ स्कूलों को मंगलवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली जो राष्ट्रीय राजधानी में इस प्रकार की एक सप्ताह में दूसरी और नौ दिनों में पांचवीं घटना है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी (शेष पृष्ठ 9)

द इंपीरियल होटल का विवाद सुलझा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के प्रतिष्ठित 'द इंपीरियल' होटल के ट्रेडमार्क से संबंधित 16 साल पुराने मुकदमे का निपटारा कर दिया। होटल के मालिक और संचालक अकोई परिवार के सदस्यों के बीच समझौता हो गया। समझौते में स्वीकार किया गया कि ट्रेडमार्क 'द इंपीरियल' का संयुक्त स्वामित्व हरदेव सिंह अकोई (50 प्रतिशत) और उनके भाई जसदेव सिंह अकोई के बच्चों, रायदेव सिंह अकोई (25 प्रतिशत) और गोविंद सिंह अकोई (25 प्रतिशत) के पास है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने आदेश में कहा, 'समझौते के अनुसार, हरदेव सिंह अकोई और स्वर्गीय जसदेव सिंह अकोई के परिवार स्वीकार करते हैं कि आज की तारीख में हरदेव सिंह अकोई [50 फीसदी], रायदेव सिंह अकोई [25 फीसदी] और गोविंद सिंह अकोई [25 फीसदी] ट्रेडमार्क इंपीरियल के संयुक्त और अनन्य मालिक हैं और कोई भी व्यक्ति अलग से ट्रेडमार्क इंपीरियल या किसी अन्य ट्रेडमार्क, व्यापार नाम, कॉपीराइट, चाहे वह पंजीकृत हो या अपंजीकृत, समान या भ्रामक रूप से समान हो, पर कोई अधिकार नहीं रखेगा या उस पर कोई अधिकार नहीं रखेगा।' नई दिल्ली स्थित इंपीरियल एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसने भारत के इतिहास में



महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा है। 1931 में स्थापित यह होटल गणमान्य व्यक्तियों और पशुपति हस्तियों के बीच समान रूप से पसंदीदा रहा है। इसकी स्थापना एसबीएस रंजीत सिंह ने की थी, जिन्होंने इसे राजदेव सिंह को दे दिया था। जसदेव और हरदेव राजदेव सिंह के बच्चे थे। इसकी परिकल्पना 1934 में की गई थी और आधिकारिक तौर पर 1936 में भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंग्डन द्वारा इसे खोला गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, होटल महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं के लिए बैकस्थल के रूप में कार्य करता था। ब्रिटिश और भारतीय नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए गोलमेज सम्मेलन यहीं आयोजित किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद, होटल राजनीतिक और सामाजिक समारोहों का केंद्र बना रहा। उच्च न्यायालय ने भी समझौते की शर्तों को वैध पाया और पुष्टि की कि ट्रेडमार्क से संबंधित कोई

अन्य विवाद लंबित नहीं था। पार्टियों ने ट्रेडमार्क या किसी भ्रामक समान चिह्नों के लिए व्यक्तिगत आवेदन या अधिकार का दावा नहीं करने पर सहमति व्यक्त की। आदेश में कहा गया है, पक्षकारों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, पारिवारिक शांति, सद्भाव और सद्भावना बनाए रखने के लिए, सभी पारिवारिक सदस्यों ने आपसी सहमति से वर्तमान मुकदमे को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारने पर सहमति व्यक्त की है। न्यायालय ने समझौते को स्वीकार करते हुए, सहमत शर्तों के आधार पर मुकदमे का आदेश दिया। इसने निर्देश दिया कि सभी पक्षों के मूल हस्ताक्षरों वाले आवेदन को केस फाइल में रखा जाए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि एक डिक्री शीट तैयार की जाए और सभी लंबित सुनवाई को रद्द कर दिया जाए। विवाद ट्रेडमार्क 'इम्पीरियल' और उसके शेर के (शेष पृष्ठ 9)

रॉन्ग साइड लेन में धरे गए सिंगर बादशाह

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम यातायात पुलिस ने सिंगर बादशाह का रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर साढ़े 15 हजार रुपये का चालान काट दिया। बादशाह यहां सेक्टर-68 में करण आहुजा के म्यूजिक कन्सर्ट में भाग लेने पहुंचे थे। वे तीन गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। बता दें कि सोनारा रोड आयरिया मॉल में रविवार को पंजाबी सिंगर करण आहुजा का लाइव कन्सर्ट था। इस कन्सर्ट में बॉलीवुड सिंगर बादशाह भी पहुंचे थे। वे एक थार गाड़ी के साथ तीन गाड़ियों के काफिले में थे। बादशाह का काफिला जैसे ही बादशाहपुर में पहुंचा तो ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना की। उनकी गाड़ियों का काफिला बादशाहपुर से



आयरिया मॉल तक रॉन्ग साइड में चला। यह सारा वाक्या सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार थार गाड़ी का नंबर एचआर-60एल-0005 है। काफिले में जो बाकी गाड़ियां थी,

उन्में टैंपेरी नंबर लगा हुआ था। जिस गाड़ी में बादशाह बैठे थे, वह गाड़ी पानीपत के दीपेंद्र माली के नाम से पंजीकृत है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि किसी को भी यातायात के नियम तोड़ने की इजाजत नहीं है। इस बीच, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक गलत साइड ड्राइविंग के लिए 1.46 लाख ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 10.28 करोड़ रुपये का चालान लगाया है, पुलिस ने कहा। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि लोग खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि गलत साइड ड्राइविंग से कई पैदल यात्रियों और अन्य मोटर चालकों की जान जा सकती है।

उमर अब्दुल्ला ने परोसा कश्मीरी वाज्वान

मोहित कंधारी। जम्मू

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को गर्मजोशी से भरी मेहमाननवाजी जम्मू-कश्मीर में सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। पिछले हफ्ते जब सीएम ने जम्मू में अपने आधिकारिक आवास पर नागरिक समाज के सदस्यों की मेजबानी की, तो उन्होंने न केवल आम नागरिकों के लिए अपने आवास के दरवाजे खोले, बल्कि कश्मीरी शेफ (वाज़ा) की एक टीम को शानदार कश्मीरी वाज्वान पकाने के लिए आमंत्रित किया, जो एक बहु-कोर्स भोजन है। काफी लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मेहमानों को जम्मू में मांसाहारी भोजन

परोसा गया। इसके अलावा, नवनिर्वाचित सीएम ने अपने आवास पर विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों, विभिन्न समितियों के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों और शिक्षाविदों के साथ-साथ अन्य प्रमुख नागरिकों की मेजबानी भी की। अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त किए जाने के बाद, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा राजभवन में आयोजित समारोहों में आम तौर पर केवल शाकाहारी भोजन/नाश्ता परोसा जाता था। केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन ने एक प्रसिद्ध स्थानीय केंटर को भी नियुक्त किया था, ताकि विभिन्न क्षेत्रों से आए मेहमानों की पसंद के अनुसार शानदार डिनर और लंच मीटिंग



आयोजित की जा सके। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न पड़ोसी राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों को भी प्राथमिकता दी गई।

नियमित मेनू में पारंपरिक मीठ कबाब और अन्य मांसाहारी व्यंजनों की जगह वेज कबाब और अन्य पाक व्यंजन शामिल किए गए। सीएम की संगति में भोजन करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए एक प्रतिष्ठित नागरिक ने पार्यन्तर को बताया, 'बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को मुख्यमंत्री खुद भोजन कक्ष में ले गए, जहां शानदार भोजन परोसा गया। उमर ने वहां मौजूद लगभग सभी लोगों से बातचीत की और उनकी बातों को ध्यान से सुना। पहले वे अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और अन्य वीवीआईपी मेहमानों के साथ व्यस्त रहते थे। लेकिन इस बार हम उमर अब्दुल्ला के एक अलग (शेष पृष्ठ 9)

दिल्ली सरकार के इमारतों में पांच स्टार रेटिंग बिजली उपकरण लगाना अनिवार्य सीएम आतिशी फाइल को मंजूरी के लिए एलजी को भेजेंगी

● इस पहल से राजधानी में बिजली खपत होने के साथ ही सालाना करोड़ों रुपये की बचत भी होगी : मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में जहां पर्यावरण प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं आम आदमी की जेब पर भी जोर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों में एनर्जी एफिशिएंट घरेलू उपकरणों की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोग अपने कार्बन फुटप्रिंट्स तो कम करना चाहते हैं साथ ही वे अपने बिजली के बिल पर भी बचत करना चाहते हैं। इसी दिशा में अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

दिल्ली सरकार ने अपनी सभी इमारतों में 5 स्टार रेटिंग एपीसी और एनर्जी एफिशिएंट पंखों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। सरकार का दावा है कि इस कदम से न केवल बिजली खपत कम होगी बल्कि सालाना करोड़ों रुपयों की बचत भी होगी। ये पहल देशभर के लिए एक



फाइल फोटो।

मिशाल बनेगी कि कैसे तकनीक के सही इस्तेमाल और बेहतर योजना के जरिए ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजेंगी।

इस बाबत जानकारी साझा करते हुए आतिशी ने कहा कि, उनकी सरकार ने ऊर्जा दक्षता को प्रार्थमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है कि सभी सरकारी इमारतों में कम बिजली इस्तेमाल करने वाले बीएलडीसी पंखे, 5-स्टार रेटेड एयर कंडीशनर और अन्य ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग अनिवार्य होगा। यह कदम न केवल बिजली खपत और बिलों को कम करेगा, बल्कि एक हरित भविष्य

की दिशा में भी बड़ा योगदान देगा। हमारा लक्ष्य है कि सरकारी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए बिजली को बचाया जाए और इस निर्णय से हर साल करोड़ों रुपये की बचत करेगी। साथ ही यह कदम पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी बड़ा योगदान देगा। मालूम हो कि दिल्ली सरकार की इमारतों बिजली की बड़ी खपतकर्ता हैं। सरकार के विभाग हर साल 2000 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं,

जिसकी लागत 8.50 रुपये से 11.50 रुपये प्रति यूनिट होती है। इस कारण से बिजली बिलों पर 1900 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होते हैं। इसी तरह, 5-स्टार रेटेड एयर कंडीशनर सामान्य एपीसी की तुलना में 2800 से 3042 यूनिट बिजली बचा सकते हैं, जो सालाना 27,000 से 29,000 रुपये की बचत का कारण बनता है। इस पहल का मुख्य मकसद बिजली की बढ़ती मांग को नियंत्रित करना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। इस साल गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग 8656 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जो पिछले वर्ष के 7438 मेगावाट के मुकाबले काफी अधिक है।

तंग गलियों में बनाया वर्ल्ड क्लास एकेडमिक ब्लॉक : सीएम

● आतिशी ने मुकुंदपुर गांव में किया उद्घाटन, बोलीं, मैंने बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन ऐसी सुविधाएं वहां भी नहीं थीं

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आप सरकार ने मुकुंदपुर गांव की तंग गलियों में बनाया स्कूल का वर्ल्ड क्लास अकेडमिक ब्लॉक। बनवाया। मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को उद्घाटन किया। साथ ही कहा कि यह निजी स्कूलों से भी शानदार है। मैंने बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन ऐसी सुविधाएं वहां भी नहीं थीं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1947 से 2015 तक सरकारी स्कूलों में 24,000 कमरे बने। आप सरकार ने



स्कूल भवन का उद्घाटन करतीं सीएम आतिशी।

मात्र 10 सालों में किया 65 सालों का काम 22,000 से ज्यादा कमरों बनाए। आप सरकार की शिक्षा नीति की अदालत अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं बनता, अच्छी शिक्षा पाकर अपने सपने पूरे करता है।

आतिशी ने कहा कि स्कूल के नए अकेडमिक ब्लॉक के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि, इतनी घनी आबादी वाले इलाके में जहाँ मात्र कुछ दूरी में ही 1 लाख को आबादी है। इतनी घनी आबादी, इतनी संकरी गलियों के

बीच इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है। आज 36 कमरों की ये बिल्डिंग इस पूरे इलाके के प्राइवेट स्कूलों में इतनी शानदार बिल्डिंग, इतने शानदार क्लासरूम, लैब नहीं मिलेंगे। नए अकेडमिक ब्लॉक से छात्रों को होगा फायदा। पढ़ाई के लिए घर से दूर नहीं जाना होगा। क्लासरूम पर कम होगा स्टूडेंट्स का दबाव पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। इस नई बिल्डिंग के बाद खासतौर पर लड़कियां जो दसवीं के बाद अक्सर दूर के स्कूलों में जाती थीं। इस नई बिल्डिंग से सबसे ज्यादा

कैग रिपोर्ट सदन में पेश नहीं करना अपराध : विजेंद्र

● बोले, सरकार ने लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की हत्या की है, सड़क से अदालत तक की लड़ाई लड़ेगा विपक्ष

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भाजपा 14 कैग रिपोर्ट्स को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कैग की रिपोर्ट्स को छुपाना, दबाना और सदन में नहीं रखना हत्या जैसा गंभीर अपराध। सरकार ने लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की हत्या की है। विपक्ष इन रिपोर्ट्स को सदन में रखवाने के लिये सड़क से अदालत तक की लड़ाई लड़ेगा। इस मुद्दे पर सरकार बेनकाब हो चुकी है। कैग की ये रिपोर्ट्स आप सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी।

विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार पर



जानबूझकर कैग की 14 रिपोर्ट्स को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बार-बार विपक्ष की मांग और उपराज्यपाल के आदेश के बावजूद इन रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए अगले 48 घंटे के अंदर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर तुरंत ही कैग की सभी 14 रिपोर्ट्स को सदन पटल पर रखने की मांग की है और कहा है कि यदि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाती है तो भाजपा फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा

‘केजरीवाल जांच के घरे में होंगे’
नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है की यह अजीब विडम्बना है की केजरीवाल ने वर्ष 2011-12 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत सीएजी रिपोर्टों को सार्वजनिक कर उन पर कार्रवाई एवं पावर डिस्कॉम की भागीदार निजी कम्पनियों के खातों की जांच मांग से की थी उन्हीं अरविंद को सरकार आज दो साल से सीएजी की रिपोर्टों को सार्वजनिक करने से बच रही है। साथ ही अब आप सरकार पावर डिस्कॉम के निजी पार्टनरों के बचाव में भी सक्रिय है।

खटखटाएगा। ताकि कोर्ट कैग की रिपोर्ट्स को विधानसभा पटल पर रखने के लिए सरकार को आवश्यक निर्देश दे।

उन्होंने कहा कि विपक्ष इन रिपोर्ट्स को सदन में रखने के लिए सरकार को विवश कर देंगे। चाहे कुछ भी हो सरकार को ये सभी रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखनी ही होंगी।

नुककड़ नाटकों के जरिए भाजपा ने केजरीवाल पर बोला हमला

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके महेनजर विभिन्न दलों की तरफ से तरह-तरह के प्रचार प्रसार के साधन अपनाए जा रहे हैं। इस कड़ी में दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नुककड़ नाटकों के जरिए निशाना साध रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है की सामान्यता भाजपा चुनाव एवं प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा के बाद सभाओं का आयोजन करती रही है पर दिल्ली वालों एवं भाजपा



कार्यकर्ताओं में केजरीवाल की अकर्मण्य एवं भ्रष्ट सरकार उखाड़ फेंकने का नया उत्साह है और उसी उत्साह ने चुनावी मौहल में पार्टी ने प्रचार नुककड़ नाटकों के माध्यम से शुरू करने को प्रोत्साहित किया है। सचदेवा ने कहा है की किसी भी

● भाजपा के चुनाव नैरेटिव को जन जन तक पहुंचा रही है नुककड़ समाएं : वीरेंद्र

नुवाव वव हव पार्टी अपना नैरेटिव सेंट करती है और भाजपा अपने पहले चरण के प्रचार में केजरीवाल सरकार की बेसिक विफलताओं को उठा रही है। दिल्ली भाजपा की नुककड़ सभा समिति के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में चुनाव नैरेटिव को जन जन तक पहुंचा रही है।

उपाध्याय के साथ 15 कार्यकर्ताओं की एक टीम रोजाना शक्ति केन्द्र स्तर यानि हर 3 से 4 पोलिंग बूथ पर एक नुककड़ सभा का आयोजन कर रही है। दिल्ली में रोजाना लगभग हर नगर निगम वार्ड स्तर पर एक सभा का आयोजन हो रहा है। सतीश उपाध्याय ने कहा है की भाजपा ने पिछले एक सप्ताह में 1812 नुककड़ सभाओं के माध्यम से गली गली तक उठाई हैं अरविंद केजरीवाल सरकार की विफलताएं। दिल्ली वाले ठप्प विकास, प्रदूषण के आलावा लवण जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्थाओं, जल जमाव एवं पेयजल संकट से परेशान है।

येलो लाइन पर बुधवार से 10 दिनों तक प्रभावित रहेगी मेट्रो सेवा

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की एलो लाइन पर जहांगीरपुरी और समयपुर बादली स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं बुधवार से दस दिनों के लिए प्रभावित रहेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यह जानकारी दी।

डीएमआरसी ने एक्स पर कहा कि जहांगीरपुरी से समयपुर बादली के बीच ट्रेन सेवाएं मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि से 28 और 29 दिसंबर की मध्यरात्रि तक रत 10.45 बजे के बाद राजस्व सेवा समाप्त होने तक और राजस्व सेवा शुरू होने से सुबह 7.02 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी। इस दौरान समयपुर बादली, रोहिणी सेक्टर-18, 19 और हैदरपुर बादली की घोषणा करेंगे, जिस पर चर्चा चल रही है। देवेन्द्र यादव ने चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, विधानसभा के कार्यकर्ता व नेताओं की सूची, मूल वोटर लिस्ट और पेन में वोटर लिस्ट

‘कांग्रेस मजबूत स्थिति में, चुनाव जीतेंगे’

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषित पहली सूची के 21 उम्मीदवार का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से दिल्ली प्रभारी मौहम्मद काजी निजामुद्दीन समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों का परिचय कराया और उनको जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी। यादव ने कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहली सूची में अनुभवी, सक्षम, युवा, महिला सभी वर्गों को समाहित कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा की है और जल्द ही अगली सूची में भी इसी तरह का समावेश सुनिश्चित करके प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, जिस पर चर्चा चल रही है।

देवेन्द्र यादव ने चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, विधानसभा के कार्यकर्ता व नेताओं की सूची, मूल वोटर लिस्ट और पेन में वोटर लिस्ट



कांग्रेस उम्मीदवारों का कमेटी के सदस्यों के परिचय के दौरान।

व अन्य जानकारी सभी 21 कांग्रेस उम्मीदवारों को देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में पूरी व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। जिसके लिए पार्टी ने त्रिप्रखर सिंह की अध्यक्षता में वार रूम बनाया है जो पूरी तरह उम्मीदवारों के साथ सहयोग करने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि नामांकन, चुनाव, कानूनी अथवा व्यक्तिगत रूप से संबंधित यदि कोई भी आपको मुश्किल होगी, आपके सहयोग और परेशानी को दूर करने का काम वार रूम करेगा। वार रूम हमेशा कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के साथ तालमेल बनाकर

रखेगा जिसके लिए एक सेंट्रलाइज नम्बर भी होगा। कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। सभी विधानसभाओं के लोगों और नेताओं को एकजुट होकर, बूथ स्तर तक के एजेंट व कार्यकर्ताओं के साथ सम्पर्क बनाकर विधानसभा में जीत का लक्ष्य साधकर जीतने के लिए चुनाव लड़ना होगा, तभी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मौहम्मद काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुश्किल समय में जो विश्वास आप लोगों पर जाताया है, वह कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं।

दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा लाभ : शिवराज चौहान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र की कृषि संबंधी योजनाओं को लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार को आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां के किसानों को महत्वपूर्ण लाभों से वंचित किया जा रहा है।

चौहान ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामबीर सिंह विधुड़ी के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को राजधानी के क्षेत्र में किसानों के फायदे के लिए केंद्र की योजनाओं को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा, वह दिल्ली

● केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा में कहा, अजून दाताओं को महत्वपूर्ण लाभों से वंचित किया जा रहा है

सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसानों के लाभ के लिए किसान केंद्रित योजनाओं को लागू करें। केंद्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए एयर सरकारों के साथ समन्वय से काम करती है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली सरकार अनेक केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं उठा रही है।

उपराज्यपाल की मौजूदगी में नष्ट किया नशीला पदार्थ

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नशा मुक्ति अभियान का उद्देश्य नशे के खतरे के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सरकार के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करना और समाज को सुरक्षित बनाना है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर नशीला पदार्थ नष्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने नशामुक्ति दिल्ली 2027 अभियान के तहत मेगा ड्रग डिस्ट्रिक्शन इवेंट आयोजित किया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार 15 दिसंबर, 2024 तक, दिल्ली में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 1,714 दवा तस्करो दर्ज किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2169 ड्रग तस्करो की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही 3.13 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, तथा 3 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति जब्त की गयी चरण में है। इसके अलावा, 7 ड्रग तस्करो के खिलाफ पीआईटीएनडीपीएस के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, जबकि 37 अन्य के खिलाफ कार्यवाही जारी है।



मादक पदार्थों को नष्ट करते उपराज्यपाल।

एलजी के मार्गदर्शन में, वर्ष 2027 तक ड्रग-मुक्त दिल्ली करने के अपने दृढ़ मिशन के अनुरूप, दिल्ली पुलिस ने ड्रग को नष्ट करने की योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को बायोटेक वेस्ट

पुलिस ने वर्ष 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त बनाने का विशेष अभियान चलाया है

सांख्यशासक प्राइवेट लिमिटेड एसएसआई औद्योगिक क्षेत्र में जब नशीले पदार्थों को नष्ट किया। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक चलेने वाली पायलट परियोजना का लक्ष्य अपराध शाखा से संबंधित लगभग 6,370.7 किग्रा नशीले पदार्थों को नष्ट करना है। इसमें गांजा (3,498.8 किग्रा), हशीश (188 किग्रा), हेरोइन (219 किग्रा), कोकेन (1.3 किग्रा), एलएसडी (13 ग्राम) व अन्य मादक पदार्थों को नष्ट किया।

लैंडफिल साइटों पर घटा ठोस अपशिष्ट कचरे का निपटान : एलजी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ओखला समेत अन्य लैंडफिल साइटों पर ठोस अपशिष्ट कचरे के जैविक उपचार की मंद और कई मामलों में घटती दर पर गंभीर चिंता और निराशा जताई। एलजी ओखला गाजीपुर और भलस्वा की लैंडफिल साइटों पर बायोरीमिडिएशन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उनके देखरेख में मई 2023 तक, केवल एक वर्ष के भीतर, कचरे निपटान की दर 1.41 लाख मीट्रिक टन प्रति माह से बढ़कर 6.5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह हो गई थी। एलजी के निरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि औसत निपटान, जो बढ़कर लगभग 22,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया था, अब



ओखला लैंडफिल साइट का अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना।

घटकर लगभग 20,000 मीट्रिक टन हो रहा गया है जबकि उपराज्यपाल ने ऐसी प्रणाली की कल्पना की थी, जिसमें ठोस अपशिष्ट कचरे का निपटान 10 लाख मीट्रिक टन प्रति माह यानी 33,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक बढ़ सके। उपराज्यपाल ने सोमवार को ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया। यह दौरा रैजिस्टर्ड वेल्फेयर एसोसिएशन, मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन, नागरिक समूहों और

जनप्रतिनिधियों द्वारा शहर की सड़कों पर खुले में पड़े कचरे और उसके निपटान में हो रही कमी के कारण उत्पन्न स्वच्छता और स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर की गई शिकायतों के बाद किया गया।

उपराज्यपाल ने सोमवार को ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया। यह दौरा रैजिस्टर्ड वेल्फेयर एसोसिएशन, मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन, नागरिक समूहों और

● उपराज्यपाल ने ओखला लैंडफिल साइट का किया निरीक्षण, जैविक उपचार की घटती दर पर चर्चाई चिंता

यह उल्लेखनीय है कि उपराज्यपाल ने शहर में ठोस अपशिष्ट कचरे के निपटान की निगरानी से खुद को अलग कर लिया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के उस आदेश पर रोक लगावा दी थी, जिसमें 11 जुलाई 2023 को यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए गठित उच्च स्तरीय

समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था।

एनजीटी ने उपराज्यपाल को ठोस कचरे के प्रबंधन और निपटान की निगरानी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था, इस मामले को आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है, और मामला अब भी लंबित है। इसके बावजूद, उपराज्यपाल ने इसे यमुना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्थान से उत्पन्न परोक्ष प्रभाव मानते हुए स्पेच्छ से ठोस कचरे के प्रबंधन के मुद्दे से पीछे हटने का निर्णय लिया।

उपराज्यपाल को अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में जैविक उपचार का कार्य बंद हो चुका है।

प्रदेश सरकार ने पेश किया 17865 करोड़ का अनुपूरक बजट

● ऊर्जा विभाग को 8587 करोड़, वित्त को 2438 करोड़, परिवार कल्याण को 1592 करोड़, पशुधन को 1001 करोड़ और पीडब्ल्यूडी के लिए 805 करोड़ रुपए प्रस्तावित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में बाधारहित विकास को अनवरत जारी रखने के लिए योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना वित्तीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। 17,865.72 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। यह योगी सरकार का इस वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट है, जो मूल बजट (7 लाख 36



हजार 437.71 करोड़ रुपए) का 2.42 प्रतिशत है। इससे पूर्व योगी सरकार 12,209.93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-

पिछली सरकार की बदनीयती के कारण नहीं की जा सकी थीं भर्तियां: सीएम

● योगी ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी रखा सरकार का पक्ष

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शिक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रखा। उन्होंने सपा विधायक मनोज कुमार पास, पूजा, पंकज पटेल के मुद्दे को महत्वपूर्ण व संवेदनशील बताया, लेकिन नसीहत दी कि सदस्यों को सदन की गरिमा व मर्यादा को ध्यान में रखकर तथ्यपरक बातें रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। हमारी सरकार ने 1.60 लाख से अधिक भर्तियां शिक्षा विभाग में की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा (बैसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, चिकित्सा शिक्षा) को लेकर नया चयन बोर्ड (उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग) बनकर तैयार है। वह विभिन्न विभागों से अध्यापन मानक नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने अकेले शिक्षा विभाग में ही 1.60 लाख से अधिक भर्तियां की हैं। यह वे भर्तियां हैं, जो पिछली सरकार की बदनीयती के कारण भरी नहीं जा सकी थीं।

आरक्षण के नियमों का हो रहा अक्षरशः पालन

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी देश, दुनिया व उत्तर प्रदेश के सामने चुनौती है। उत्तर प्रदेश दुनिया के अंदर सबसे युवा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 56 से 60 फीसदी आबादी वर्किंग फोर्स-युवा है। हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को ध्यान में रखकर अनेक कार्य किए हैं। पिछले सत्र में हमारी सरकार ने पेर लीक की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा व अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम - 2024 को पारित किया। प्रदेश के युवाओं को ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां प्राप्त हो रही हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का

इस वित्तीय वर्ष में दूसरी बार प्रस्तुत किया अनुपूरक बजट, 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव किए गए हैं सम्मिलित

उपस्थिति में विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट का आकार 17,865.72 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि यह सरकार विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है और जब भी आवश्यकता होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही इसमें केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रीय राशि भी अनुमानित है। इसके अतिरिक्त, कंटेजिंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपए का पैसा लिया गया था, उसकी भी प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव इसमें शामिल है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप बजट जारी किया जाएगा।

25 का कुल बजट अब 7 लाख 66 हजार 513.36 करोड़ रुपए का हो गया है। योगी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की

सदस्यों द्वारा रखे गए आंकड़े तथ्यपरक नहीं हैं। यदि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी व माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भर्तियों की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात है तो 69000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं, वे सभी चार वर्षों से स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। उससे पहले 68500 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया गया, क्योंकि उस समय तथ्यपरक बातें रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। हमारी सरकार ने 1.60 लाख से अधिक भर्तियां शिक्षा विभाग में की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा (बैसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, चिकित्सा शिक्षा) को लेकर नया चयन बोर्ड (उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग) बनकर तैयार है। वह विभिन्न विभागों से अध्यापन मानक नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने अकेले शिक्षा विभाग में ही 1.60 लाख से अधिक भर्तियां की हैं। यह वे भर्तियां हैं, जो पिछली सरकार की बदनीयती के कारण भरी नहीं जा सकी थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया था। शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें खारिज करके सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें निश्चित मादयेय पर रखा है। वे सभी शिक्षामित्र भी यथावत कार्य कर रहे हैं। उन्हें वेतन देकर भर्ती प्रक्रिया से जोड़ा गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा के अनुरूप कदम उठाए गए थे। 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड व उच्चतर शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा संपन्न की जा चुकी है।

सीएम ने कराया हकीकत से वाकफ

मुख्यमंत्री ने कहा कि 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ी विमर्श से कहीं का पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 18 हजार पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं।

विपक्ष ने उठाया बिजली के निजीकरण का मामला, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए

● ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले, सरकार आम जनता के साथ ही कर्मचारियों का भी रख रही ध्यान

● जबाब से असंतुष्ट कांग्रेस सदस्यों ने सदन से किया वाकआउट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने बिजली के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। सपा सदस्य ओमप्रकाश सिंह, नफीस मलिक, आर के सिंह, कमाल अख्तर, कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना ने सरकार द्वारा बिजली को निजी हाथों में दिए जाने का मामला उठाया। इन

योगी सरकार में कानून व्यवस्था सबसे मजबूत: खन्ना

● विपक्ष की ओर से गलत आंकड़े पेश करने पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में दिया कराया जवाब

लगातार कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2017 में 2524 मामले सामने आए थे। 1 जनवरी 2024 से 31 अक्टूबर तक इस पर 1418 केस दर्ज किए गए। वर्ष 2023 में दहेज मृत्यु की 2061 घटनाएं दर्ज की गईं। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने में भी प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा सफल हुई है। उन्होंने विपक्ष के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर के बीच 1090 विषम पावर लाइन व 4,18,504 शिकायतें दर्ज की गईं। इसमें 4 लाख 9 हजार 912 शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसका रैशु 97.95 प्रतिशत है। वहीं रैशु 8,592 मामलों के निस्तारण के लिए कार्रवाई की जा रही है।

कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि दहेज मृत्यु के मामले में भी

विपक्ष ने उठाया बिजली के निजीकरण का मामला, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए



सदस्यों ने कहा कि बिजली के निजीकरण से जहां विभाग के हजारों कर्मचारी सड़क पर आ जायेंगे। बिजली की दरे बढ़ जायेंगे। जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस की सदस्य आराधना मिश्रा मोना ने इस मुद्दे पर सरकार से, स्वेतपत्र लाए जाने की मांग की। सपा कांग्रेस सदस्यों के जवाब में उर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की संकाए निर्मूल है। इस बारे में सरकार

विपक्ष की ओर से गलत आंकड़े पेश करने पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में दिया कराया जवाब

और 2023 में 2841 और अभी इस वर्ष 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक 2440 लोगों को सजा दिलाने में सफलता हासिल की गई। स्पेशल अभियान चलाकर 1 जुलाई 2023 से लेकर 11 दिसंबर 2024 तक 48 म्यूटर्न दिए गए। इसी अवधि में 6065 मामलों में आजीवन कारावास, 1046 मामलों में 20 वर्ष और उससे अधिक सजा, 73 मामलों में 15 से 19 वर्ष की सजा, 3610 मामलों में 10 से 14 वर्ष की सजा, 5564 मामलों में 5 से 9 वर्ष की सजा और 22298 मामलों में पांच वर्ष से कम की सजा दिलाने में सफलता मिली। सुरेश खन्ना ने कहा कि जब से भारतीय न्याय संहिता आई, इसमें 1 जुलाई से लेकर 12 दिसंबर तक 29 लोगों को सजा हुई है। सुरेश खन्ना ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट उपलब्ध है, उसके मुताबिक हर क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित अपराध में गिरावट दर्ज की गई है। दुष्कर्म के मामले में पूरे देश में यूपी का 24वां स्थान है।

कांग्रेस नेता फिलीस्तीन का बैग लेकर घूम रही, हम नौजवानों को इजराइल भेज रहे: योगी



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सीएम योगी ने बिना नाम लिए प्रियंका गांधी वाड़ा पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को अपने वक्तव्य के दौरान कई बार विपक्षी सदस्यों पर करारे कटाक्ष किए। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस की एक नेता संसद में फिलीस्तीन का बैग लेकर घूम रही थीं और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। सीएम योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को सरकार की योजनाओं और नीतियों को समझने का भी सुझाव दिया। बोले- प्रदेश के नौजवानों के हितों के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। विपक्ष के सदस्य यदि सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में समझकर अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे तो उनके क्षेत्र के नौजवानों का ही भला होगा और उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो वही होगा जो कुंदरकी में हुआ है।

सीएम योगी बोले, हमें उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। सदन में कुम्भ पर भी चर्चा होगी और मुझे लगता है कुम्भ हमारे लिए एक अवसर होगा उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर शोकेस करने का, लेकिन इसके लिए अच्छा बोलना और सोचना पड़ेगा। नकारात्मकता को हटाना पड़ेगा। विपक्ष का मतलब नकारात्मक नहीं हो सकता है। विपक्ष का मतलब हर चीज में खुराई करना नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा सोचिए, अच्छी दिशा में चलिए, अच्छी दिशा में चलेंगे तो आगे अच्छा ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई ही मिलेगी। नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सीएम ने विपक्ष को आत्मनिर्भर से आग्रह किया सदन में आकर मुद्दों को रखें, लेकिन तथ्यों के साथ रखें तो उनकी गरिमा और सम्मान बढ़ेगा। उनके मुद्दे उचित, लेकिन तथ्यहीन-अपुष्ट थे। उन्होंने अपील की कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और विद्वेष को छोड़कर सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो अपने क्षेत्र के नौजवानों का भला कर पाएंगे। नहीं तो आपका वही हाल होगा जो कुंदरकी में हुआ।

सीएम के निर्देश पर राहत आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को भेजा परिपत्र

न सोये, उन्हें निकटम रैन बसेरों में विस्थापित किया जाए। राहत आयुक्त के परिपत्र के अनुसार नगरखुर् जिला प्रशासन ने नगर मजिस्ट्रेट, सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम और सभी तहसीलदारों को रात्रिकालीन अभियान में जुटने को निर्देशित किया है। गोरखपुर के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं आपदा के प्रभारी अधिकारी विनीत कुमार सिंह के मुताबिक बढ़ते शीतलहर को देखते हुए रैन बसेरों में आश्रय दिया जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर प्रशासन के अफसरों ने रात्रिकालीन निरीक्षण और भ्रमण का अभियान चलाकर खुले आसमान तले मिलने वाले गरीबों और असहायों को रैन बसेरों में सम्मानजनक तरीके से आश्रय देने की पहल की है। उंड के प्रतिकूल मौसम में गरीबों और निराश्रितों को सुविधा व सहायता के लिए मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए दिशानिर्देश के क्रम में प्रदेश के राहत आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर कहा है कि शीतलहर के दौरान कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे

‘एक देश-एक चुनाव’ का फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक: अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 'एक देश-एक चुनाव' का फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। ये देश के संघीय ढांचे पर भी एक बड़ा चोट करेगा। इससे क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व खत्म हो जाएगा और जनता उन बड़े दिखावटी मुद्दों के मायाजाल में फंसकर रह जाएगी, जिन तक उनकी पहुँच ही नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संदर्भों में 'एक' शब्द ही अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र बहुलता का पक्षधर होता है। 'एक' की भावना में दूसरे के लिए स्थान नहीं होता। जिससे सामाजिक सहनशीलता का हनन होता है। व्यक्तिगत स्तर पर 'एक' का भाव, अहंकार को जन्म देता है और सत्ता को तानाशाही बना देता है। अखिलेश ने कहा कि एक तरह से ये संविधान को खत्म करने का एक और षड्यंत्र भी है। इससे

राज्यों का महत्व भी घटेगा और राज्यसभा का भी। कल को ये भाजपा वाले राज्यसभा को मूल मानते हुए ही 'राज्यसभा' की निरंतरता का संवैधानिक प्रावधान है। लोकसभा तो पाँच वर्ष तक की समयवधि के लिए होती है। अखिलेश ने प्रश्न किया कि क्या 'एक देश, एक चुनाव' का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी से बड़ा मुद्दा है जो भाजपाई इसे उठा रहे हैं। दरअसल भाजपा इन बड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही है। जनता सच समझ रही है। सच तो ये है कि बीजेपी को तो सोते-जागते सिर्फ चुनाव दिखाई देता है, और ये सोचते हैं कि किस तिकड़म से परिणाम इनके पक्ष में दिखाई दे।

कांग्रेस के विधानसभा घेराव कार्यक्रम से घबराई है योगी सरकार: अजय राय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस के विधानसभा घेराव कार्यक्रम से घबराई योगी सरकार पुलिस के माध्यम से कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर विधानसभा घेराव में शामिल होने पर आने के लिए रोक रही है। प्रदेश के अधिक से अधिक जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर धरने में शामिल होने से रोकना जा रहा है जो कि निहायत ही शर्मनाक और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह सरकार तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर आम जनता की आवाज को कुचल रही है। हम कांग्रेस के लोग इनकी साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरह से यह कल के कांग्रेस के विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर पुलिस तंत्र

पुलिस के माध्यम से कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं को डरा-धमकाकर रोकने का लगाया आरोप

का इस्तेमाल करके हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, रोक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से इसका जवाब देगी और प्रदेश व्यापी आंदोलन खड़ा करेगी।

अजय राय ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार के तानाशाही रवैये, बेरोजगारी, महंगाई, जैसे मुद्दे पर सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है। चाहे जितनी नुकुली बैरिकेडिंग सरकार कांग्रेसियों को रोकने के लिए लगाए लेकिन अब कांग्रेसी भाजपा के इस कुशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मन बना चुका है।

युवा कांग्रेस के कार्यक्रम 'यंग इंडिया के बोल' सीजन-5 की शुरुआत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा युवाओं को उनकी प्रतिभा को उभारने के लिए तैयार किए गए मंच 'यंग इंडिया के बोल' कार्यक्रम के सीजन-5 की शुरुआत की गई तथा यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का पोस्टर भी लांच किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह एवं दिनेश कुमार सिंह, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस विनीत कम्बोज, युवा कांग्रेस मध्य के का. अध्यक्ष अंकित तिवारी मौजूद रहे। प्रदेश

पुलिस के माध्यम से कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं को डरा-धमकाकर रोकने का लगाया आरोप

का इस्तेमाल करके हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, रोक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से इसका जवाब देगी और प्रदेश व्यापी आंदोलन खड़ा करेगी।

अजय राय ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार के तानाशाही रवैये, बेरोजगारी, महंगाई, जैसे मुद्दे पर सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है। चाहे जितनी नुकुली बैरिकेडिंग सरकार कांग्रेसियों को रोकने के लिए लगाए लेकिन अब युवा भाजपा के इस कुशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मन बना चुका है।

